Live Law @LiveLawIndia · 1h

"Nobody can tell a (stray) dog or a tiger what its territorial limits are...we had this problem in the Bombay Hight Court. We solved it by feeding them. Now they just sleep."

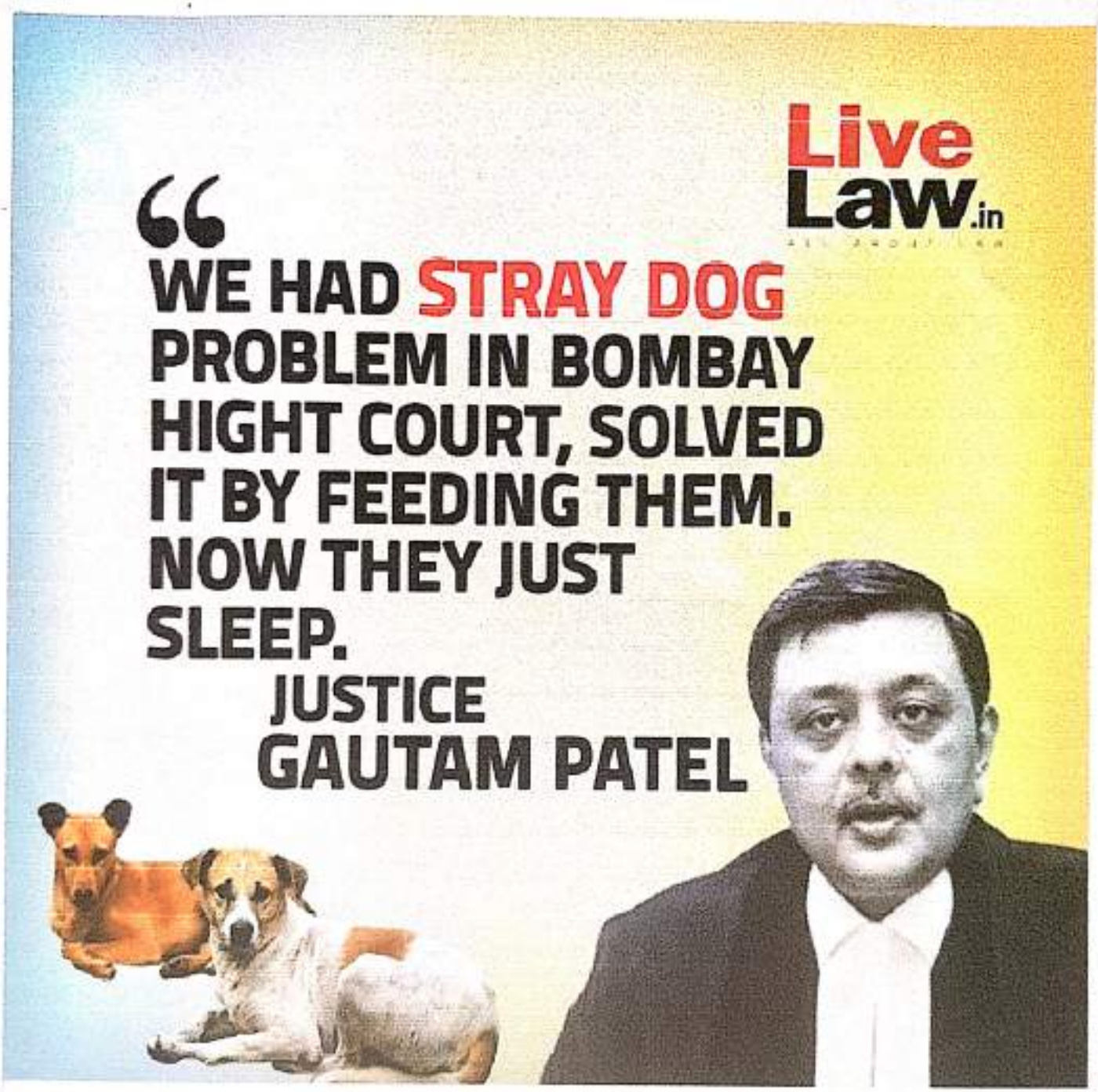

11:35 am · 23 Feb 23 from Panchkula, India · 33 Views

Scanned with OKEN Scanner

नवभारत

आवारा कुत्तों की होगी गणना

महानगरपालिका ने आबादी नियंत्रण हेतु लिया निर्णय

60 हजार कुत्तों की प्रतिवर्ष हत्या करती थी गनपा

2013 में हुई स्टडी में कुल 95,172 कुत्तों की गणना

2023 से शुरू होगा अभियान

■ मुंबई, नवभारत न्यूज नेटवर्क. शहर में बढ़ते आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रण करने के लिए मुंबई महानगरपालिका ने उनकी गणना करने का प्रस्ताव रखा है. इन पशुओं की गणना के जरिये बीएमसी इस बात का अनुमान लगाएगी कि उन्हें इसमें किस स्तर पर हस्तक्षेप करना होगा? इसके लिए पहले की तरह ही बीएमसी एक बाहरी वाइल्ड वेलफेयर टीम को चुनेगी जो उनके कुल 24 वार्ड में मौजूद आवारा कुत्तों की गणना करके एक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें इन पशुओं की अनुमानित उम्र, उनका सेक्स रेश्यो, प्रजनन की स्थिति और उनकी स्वास्थ्य की जानकारी मौजूद होगी. इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बीएमसी आबादी नियंत्रण को लेकर अपने फैसले तैयार करेगी.

महाराष्ट्र एनिमल वेलफेयर बोर्ड की पूर्व सदस्य एडवोकेट सिद्ध विद्या ने कहा कि एनिमल बिर्थ कंट्रोल (एबीसी) प्रोग्राम से ही रेबीज जैसी समस्या को सुलझाया जा सकता है और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया है.

बढ़ती आबादी से लोग परेशान

बीएमसी की इस पहल पर बात करते हुए डॉ. कलीम पठान (हेड ऑफ वेटरनरी सर्विसेज डिपार्टमेंट) ने कहा, 'ऐसा ही सर्वे 2013 में किया गया था. ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल द्वारा की गई एक स्टडी में कुल 95,172 कुत्तों की गणना की गई थी, हालांकि ये संख्या असल तादाद से कम बताई जा रही.

कोई प्लान नहीं

प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण प्लान न होने के चलते शहर में आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है. इसके चलते कुत्तों द्वारा हमले के मामले बढ़े हैं और साथ ही एंटी-रेबीज वैक्सीन की मांग भी बढ़ी है.

BMC के पास टीम नहीं

रिसिंक एसोसिएशन फॉर वाइल्ड वेलफेयर के प्रेसिडेंट पवन शर्मा ने कहा कि ये परेशानियां इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि इस कार्य को बीएमसी स्वयं नहीं संभालती है. पशुओं की आबादी को नियंत्रण करने के लिए टीम क्यों नहीं है?

10 लाख होंगे खर्च

डॉ. कलीम पठान ने बताया कि इस ताजा सर्वे के लिए बीएमसी करीब 10 लाख रूपए खर्च करेगी और ये सर्वे अगले साल से शुरू होकर 4 महीनों तक चलेगा.

पहले बीएमसी कुत्तों की संख्या कम करने के लिए हर वर्ष 55 से 60 हजार कुत्तों की हत्या करती थी. इसे लेकर मेरे पास उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया गया एफिडेविट भी है. ये सर्वे हर साल किया जाना चाहिए था लेकिन इसमें लापरवाही बरती गई है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एनिमल कंट्रोल और उनके प्रोटेक्शन के लिए एनिमल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए लेकिन तथा इसका पालन किया गया? इस संदर्भ में अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है. अगर एबीसी का गठन होता तो डॉग बाईट और आवारा कुत्तों से जुड़ी अन्य समस्याओं को भी काफी हद तक कम किया जा सकता था.

Mumbai Edition
21-december-2022 Page No. 2
epaper.navabharat.com

Scanned with OKEN Scanner